Small Industries Corporation. State Governments provide marketing support through State Small Industries Development Corporation.

(4) Provision of infrastructural support is the responsibility of the State Governments who make available developed industrial plots, sheds, etc.

(5) Central Government is also concerned with the provision of finance through financial institutions to the sick industrial units in their rehabilitation programmes. The steps taken/proposed to be taken to revive the sick units to take care of the financial problems are as under:—

(i) Issuance of detailed guidelines by RBI to all scheduled commercial banks in regard to rehabilitation of sick units.

(ii) Financial assistance in the form of long term equity type assistance upto Rs. 1,50,000/- to units with a project cost not exceeding Rs. 10 lakhs at a nominal service charge of one percent per annum is also available to potentially viable sick SSI units from the National Equity Fund set up in August, 1987.

(iii) At the instance of the Central Government, the RBI had constituted a Committee under the Chairmanship of Ex-Deputy Governor, Shri P. R. Nayak. which submitted its report in September, 1992. The Committee looked into the problems of credit, sickness and other relevant aspects. The Committee has made several recommendation for the revival of sick units which include a modified definition of sick SSI Units, creation of separate cells by banks, setting up of State Level Tribunals, use of DICs as a forum for redressal of grievances, revitalisation of State Level Inter-Institutional Committees, etc. The RBI has already announced its decision on some of its recommendations such as modified definition of sick units and reduced rate of interest to be charged on the rehabilitation of sick units.

(iv) RBI has decided that SSI sector would be getting upto 20 per cent of their output by way of working capital loan.

(v) SSI forms part of the priority sector lending programme of the banks.

Setting up of Export Development Centre

7038. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Export Development Centre has been set up in the Small Industries Development Organization;

(b) if so, what are the functions thereof; and

(c) what has been the Centre's performance, till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

7039. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सूरत, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, वापी, भरूच तथा बलसाड में महत्वपूर्ण भारी उद्योग स्थापित किये जाने संबंधी अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार ने उपरोक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के बजट के दौरान उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये वर्ष 1991 से 1993 के बीच प्राप्त आवेदनों की संख्या और उनके निपटान की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:—

जिले का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटान की स्थिति (1-4-94 को)		
		जारी किये गये आशय पत्र	अस्वीकृत	वापिस लिये/ लाइसेंस जरूरी नहीं
1	2	3	4	5
सूरत	47	36	5	6
बड़ौदा/बडोदरा	68	45	15	7
अंकलेश्वर	—	—	—	—
वापी	—	—	—	—
भड़ौंच	86	63	11	11
वालसाड़	44	24	8	9

(घ) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों को जल्दी निपटाने का भरसक प्रयत्न किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय की क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में इनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा पूरी जानकारी दिये जाने पर भी निर्भर करता है।

लघु उद्योगों के विकास की दर

7040. श्री राम जेठमलानी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में लघु उद्योगों के विकास की दर क्या रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से लघु उद्योगों के विकास की दर में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुये लघु उद्योगों के विकास की दर में वृद्धि करने के कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कितने लघु उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के.